भगतसिंह जनअधिकार यात्रा

बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और मेहनतकश जनता की लूट के खिलाफ़!

रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जुझारू जनएकजुटता के लिए!

भाजपा के "रामराज्य" में भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान

सहयोग राशि : 10 रुपये

"क़ानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वह जनता के दिल यानी भावनाओं को प्रकट करता है। जब यह शोषणकारी समूह के हाथों में एक पुर्ज़ा बन जाता है तब अपनी पवित्रता और महत्त्व खो बैठता है। न्याय प्रदान करने के लिए मूल बात यह है कि हर तरह के लाभ या हित का ख़ात्मा होना चाहिए। ज्यों ही क़ानून सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना बन्द कर देता है त्यों ही ज़ुल्म और अन्याय को बढ़ाने का हथियार बन जाता है। ऐसे क़ानूनों को जारी रखना सामूहिक हितों पर विशेष हितों की दम्भपूर्ण ज़बरदस्ती के सिवाय कुछ नहीं है।"

-- शहीदे-आज़म भगतसिंह

भगतसिंह जनअधिकार यात्रा के लिए नौभास के योगेश द्वारा प्रोग्रेसिव प्रिण्टर्स, दिल्ली से प्रकाशित, 4 मई, 2023

पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में घपलों-घोटालों के कीर्तिमान ध्वस्त हो गये हैं। राफेल घोटाला, पीएम केयर घोटाला, एनपीए घोटाला, व्यापम घोटाला, अडानी घोटाला... फ़ेहरिस्त लम्बी है। यह दीगर बात है कि पहले के घोटालों जैसे कि बोफ़ोर्स घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2जी घोटाला, आदि पर जितना शोर मचता था, वह आज नहीं मचता। वजह यह है कि समूचा मीडिया आज मोदी सरकार की गोद में बैठा है जो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को भी सदाचार की मिसाल बनाकर पेश करता है। ऊपर से संघ परिवार का प्रचार तन्त्र हिटलर के प्रचार तन्त्र के पदचिह्नों पर ही चलते हुए एक झूठ को सौ बार दुहराकर सच बना देता है! न्यायपालिका, पुलिस, सेना, नौकरशाही तक में अपने लोगों को संघ परिवार पिछले कई दशकों से बिठाता रहा है और आज नतीजा सामने है। सारी संस्थाएँ जो धन्नासेठों की मुनाफ़ाखोरी को समर्पित मौजूदा व्यवस्था में थोड़ा सन्तुलन बनाये रखने का काम करती थीं, वे आज मोदी-शाह की जेब में हैं। इसलिए मोदी सरकार ने जो रिकार्डतोड़ भ्रष्टाचार किया है उसकी पूरी तस्वीर को लोगों के सामने आने नहीं दिया जाता है।

लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। अभूतपूर्व घपलों-घोटालों का सिलसिला अब उस जगह पहुँच गया है कि विदेशों में भी "विश्व-गुरू" का डंका बज गया है! ऐसे में, इन घपलों-घोटालों को पूरी तरह से छिपाना मोदी सरकार और संघ परिवार के लिए मुश्किल हो गया है।

महँगाई, बेरोज़गारी और भुखमरी से त्रस्त आम जनता को तो मोदी सरकार बोलती है कि विकास के लिए कुछ समय के लिए हम अधिकार भूल जायें और केवल कर्तव्य की बात करें! हमें संघ परिवार और भाजपा "संस्कार", "संस्कृति", "राष्ट्रवाद" और "देशभक्ति" की नसीहतें देती है और कहती है कि हम "रामराज्य" लाने के लिए पेट पर पट्टी बाँध लें और त्याग करें! हमें "सन्तोषम् परम सुखम" का उपदेश दिया जाता है! वहीं दूसरी ओर अडानियों-अम्बानियों को और भाजपा के नेता-मन्त्रियों को तिजोरियाँ और पेट ठूँस-ठूँसकर भरने के लिए भ्रष्टाचार करने का पूरा अवसर दिया जाता है। ऐसे में, जिस "चाल-चेहरा-चरित्र" की दुहाई भाजपा और संघ परिवार हमेशा दिया करते थे, उसकी कलई पूरी तरह से खुल गयी है।

वैसे तो मौजूदा मुनाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था अपने आप में घोटालों और भ्रष्टाचार का अन्तहीन चक्र है। देश में आज़ादी के बाद से ही घोटालों और भ्रष्टाचार का इतिहास रहा

है। *जो व्यवस्था बाक़ायदा मुनाफ़ाखोरी को बढ़ावा दे, जो व्यक्तिगत लाभ को सर्वोच्च बताये, जो साम-दाम-दण्ड-भेद से धन और सत्ता को हासिल करने को ही लक्ष्य बताये, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व वितरण न करे, बल्कि जिसमें मुट्ठी भर धन्नासेठों के मुनाफ़े से संचालित उत्पादन व वितरण हो, जहाँ मुनाफ़े की अन्धी हवस का ही राज हो, वहाँ मुनाफ़ाखोरी केवल क़ानूनी सीमा में सीमित थोड़े ही रहेगी!* वैसे तो देश के सारे कल-कारखानों, खानों-खदानों और खेतों-खलिहानों पर बड़े-बड़े सेठों-व्यापारियों, ठेकेदारों और दलालों का कब्ज़ा होना भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार ही है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को 'मुनाफ़ा कमाने की आज़ादी' के नाम पर क़ानूनी मान्यता प्राप्त है। वैसे तो सुई से लेकर जहाज़ बनाने वाले मज़दूरों को देश की सारी धन-दौलत और सम्पदा पैदा करने के बाद भुखमरी के स्तर पर जीवित रहने लायक ख़ुराक देकर दिनों-रात हाड़तोड़ मेहनत करवाना और उसकी मेहनत के फल को मुट्ठी भर मालिकों द्वारा हड़प लिया जाना भी भ्रष्टाचार है, लेकिन इसे भी क़ानूनी मान्यता प्राप्त है। **क़ानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त यह शोषण भी भ्रष्टाचार है, लेकिन जिस व्यवस्था के केन्द्र में सीधी उंगली या टेढ़ी उंगली करके मुनाफ़ा पीटना ही सबकुछ हो, वहाँ इन मालिकों, ठेकेदारों, व्यापारियों, बिचौलियों, धनी फार्मरों और ज़मीन्दारों की मुनाफ़े की हवस क़ानूनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है और खुले, नंगे भ्रष्टाचार के रूप में प्रकट होती है, यानी रिश्वतखोरी, घूसखोरी, सरकारी अधिकारियों को ख़रीदना, टेण्डर घोटाले, कीमतों के हेराफेरी के ज़रिये ख़रीद घोटाले, कमीशनखोरी, आदि।**

और मोदी जी की "संस्कारी", "धर्मध्वजाधारी", "राष्ट्रवादी" भाजपा सरकार ने इस खुले, नंगे भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं। भाजपा सरकार के आने के बाद से भ्रष्टाचार के इन आँकड़ों में कई गुना की वृद्धि हुई है। हाल ही में हिण्डेनबर्ग द्वारा किये गये ख़ुलासे ने न केवल मोदी सरकार और अडाणी के बीच के भ्रष्टाचारी गठजोड़ की कलई खोलकर रख दी है, बल्कि भाजपाई 'सदाचार', 'राष्ट्रवाद', 'विकास' आदि जुमलों की भी हक़ीक़त का पर्दाफ़ाश कर दिया है। इसके पहले भी मामला चाहे **पीएमकेयर घोटाले** का रहा हो, **राफेल घोटाले** का रहा हो या **सेण्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट घोटाले** का रहा हो; हर जगह भाजपा सरकार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार ने पुराने घपलों-घोटालों को बौना दिखाकर शर्मिन्दा कर दिया। भाजपा सरकार ने 'देशभक्ति' के शोर के नीचे इन घोटालों को छिपा लिया, या हिन्दू-मुसलमान, मन्दिर-

मस्जिद, 'लव जिहाद', 'गोरक्षा', आदि के फ़र्ज़ी शोर में इन्हें दबा दिया।

हालाँकि भाजपा के अलावा भी केन्द्र में बैठी पिछली सभी पार्टियों की सरकारों ने और अलग-अलग राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टियों ने भी भ्रष्टाचार करने और जनता को लूटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने दावे के अनुरूप ही 'सत्तर सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये' और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान खड़ा कर दिया। आज मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में 'बहुत सह लिया भ्रष्टाचार अबकी बार मोदी सरकार' और 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' जैसे नारों की पोल खुल चुकी है।

हम अपने बहुत सामान्य अनुभव से भी जानते हैं कि इस व्यवस्था में यदि कोई पंचायत के चुनावों में भी किसी पद पर जीत जाता है तो उसकी पीढ़ियों का इन्तज़ाम हो जाता है, विधायकों-सांसदों-मन्त्रियों की तो बात ही अलग है। इसकी वज़ह यह है कि मौजूदा व्यवस्था जिसे हम लोकतन्त्र कहते हैं, वह असल में मुट्ठी भर बड़े धन्नासेठों, अमीरज़ादों, मालिकों, ठेकेदारों, बड़े दुकानदारों, बिल्डरों, धनी फ़ार्मरों आदि के एक वर्ग की बहुसंख्यक आम मेहनतक़श जनता के ऊपर तानाशाही ही होती है। सरकारें जब "राष्ट्र के विकास" और "राष्ट्र के हित" की बात करती हैं, तो असल में वह इन्हीं मुट्ठी भर लुटेरों के विकास और हितों की बात कर रही होती हैं क्योंकि उनके "राष्ट्र" की परिभाषा में देश की बहुसंख्यक मेहनतक़श आबादी नहीं आती बल्कि उनके लिए "राष्ट्र" का मतलब अम्बानी, अडाणी, टाटा, बिड़ला जैसे बड़े धन्नासेठ होते हैं और "राष्ट्र" का हित उनका मुनाफ़ा होता है। हमें तो बस "राष्ट्रहित" में ठेके पर खटना होता है, ताकि इन धनपशुओं की तिजोरियों में हमारा ख़ून सिक्कों में ढलकर भरता रहे! यह सच्चाई तब सामने आ गयी जब अडाणी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली हिण्डेनबर्ग रिपोर्ट को अडाणी और मोदी सरकार द्वारा "राष्ट्र पर हमला" बताया गया! इसी से पता चल गया कि मौजूदा व्यवस्था में "राष्ट्र" और कुछ नहीं धन्नासेठों और अमीरज़ादों की पूरी जमात है।

इसी तरह भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार को मिटाने और कालाधन को समाप्त करने के नाम पर 'नोटबन्दी' और 'जीएसटी' जैसे क़दम उठाये गये। इन क़दमों के बाद कालाधन वापस आना तो दूर की बात है, आम जनता की जेब में जो कुछ भी था, वह भी निकलकर पूँजीपतियों की तिज़ोरी में समा चुका है। 'नोटबन्दी' और 'जीएसटी' के बाद देश के बड़े धन्नासेठों की सम्पत्ति में अरबों-

खरबों की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। दूसरी ओर आम जनता, जिसको लाइन में लगाने के बाद "पचास दिनों के भीतर देश का कायाकल्प" करने का सपना दिखाया गया था; उसकी कंगाली और तबाही-बदहाली और ज़्यादा बढ़ी है।

वास्तव में, नोटबन्दी ख़ुद आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। नोटबन्दी के बाद काला धन कहाँ पकड़ आया? लगभग 99 प्रतिशत नोट तो वापस बैंक में आ गये! यानी, जिनके पास काला धन था उन्होंने भी उसे मोदी जी की कृपा से सफ़ेद में तब्दील कर लिया। वहीं छोटी पूँजी को नोटबन्दी ने काफ़ी तबाह किया, जिसके बूते बड़ी पूँजी जैसे अडानी-अम्बानी, टाटा-बिड़ला के लिए बाज़ार ख़ाली करवाया गया। नोटबन्दी का असली मक़सद भी यही दोनों काम था, जिसके लिए देश की जनता को इतनी तक़लीफ़ें उठानी पड़ीं और सैंकड़ों लोगों की जान तक चली गयी। लेकिन गोदी मीडिया के प्रचार-तन्त्र ने इस अपराध को छिपाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए शोर-गुल, नौटंकी और भंड़ैती का ऐसा कुचक्र चलाया कि मोदी सरकार का यह भयंकर भ्रष्टाचार भी एक "राष्ट्रवादी कार्रवाई" बन गया!

भाजपा सरकार के विराट घपलों-घोटालों में से कुछ पर ग़ौर करिये।

हिण्डेनबर्ग ख़ुलासा और अडाणी-मोदी सरकार घोटाला

हाल ही में एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर संस्था हिण्डेनबर्ग द्वारा अडाणी की कम्पनियों को लेकर किये गये ख़ुलासे ने भाजपा द्वारा किये गये घोटालों और भ्रष्टाचार के काले इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस खुलासे में हिण्डेनबर्ग ने आँकड़ों और तथ्यों के ज़रिये साबित किया कि अडाणी ने भाजपा सरकार के "रामराज्य" में बहुत कम समय में जो पूँजी का अकूत पहाड़ खड़ा किया है, वह असल में दशकों से **स्टॉक क़ीमतों और बही-खातों में हेराफेरी, विदेशी 'टैक्स हैवेन' में अपने परिजनों द्वारा संचालित फ़र्ज़ी शेल कम्पनियों द्वारा अपने ही पैसे को अपनी कम्पनी में फ़िर से निवेश करके उसके शेयर की क़ीमतों को बढ़ाने और इन बढ़ी हुई क़ीमतों के ज़रिये देश और दुनिया की तमाम वित्तीय संस्थाओं से भारी-भरकम क़र्ज़ लेने की तिकड़म काम कर रही है।**

हिण्डेनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह की कम्पनियों पर 2 वर्ष तक किये गये अपने शोध की रिपोर्ट में दावा किया है कि अडाणी समूह की 7 लिस्टेड कम्पनियों के स्टॉक में पिछले 3 वर्षों के दौरान जो औसतन 819 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है वह जालसाज़ी

के ज़रिये हुई है। इस जालसाज़ी का तरीक़ा बताते हुए रिपोर्ट में प्रमाणों के साथ दिखाया गया है कि अडाणी समूह ने 'टैक्स हैवेन' कहे जाने वाले मॉरीशस, साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियाई द्वीप समूह के तमाम देशों में फ़र्ज़ी शेल कम्पनियों का जाल बिछाया है जिन्हें **गौतम अडाणी का बड़ा भाई विनोद अडाणी** नियन्त्रित करता है। विदेशों में मौजूद इन फ़र्ज़ी कम्पनियों में ग़ैर-क़ानूनी रूप से अडाणी समूह का ही पैसा लगा है और इसी पैसे से वापस भारत में अडाणी की ही लिस्टेड कम्पनियों के शेयर ख़रीदे जाते हैं और इस प्रकार इन कम्पनियों के शेयर की माँग में बढ़ोत्तरी करके उसके दाम को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। भारतीय शेयर बाज़ार के विनियामक सेबी (सिक्योरिटीज़ ऐण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इण्डिया) के नियम के अनुसार किसी लिस्टेड कम्पनी के शेयरों में प्रमोटर्स का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन शेल कम्पनियों के उपरोक्त फ़र्ज़ीवाड़े की मदद से अडाणी की 7 लिस्टेड कम्पनियों में अडाणी परिवार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कहीं ज़्यादा हो जाती है।

यही नहीं अडाणी समूह अपनी कम्पनियों के शेयर की ऊँची क़ीमतें और उनकी अच्छी सेहत दिखाकर देशी व विदेशी वित्तीय संस्थाओं से भारी क़र्ज़ा भी लेता रहा है जिसकी राशि उसकी वास्तविक परिसम्पत्तियों के मूल्य की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार अडाणी समूह की कम्पनियों के शेयर के दाम उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं बल्कि उनकी वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने का काम करते हैं। यह सट्टेबाज़ी द्वारा फुलाया गया बुलबुला है, जिसके बूते पर सरकारी बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से भी अडाणी ने जनता की गाढ़ी कमाई के लाखों-करोड़ ऋण के तौर पर लिए हैं। **क्या यह मोदी सरकार की मिलीभगत के बिना सम्भव है? ख़ुद सोचिये। ऐसा होता है क्या?**

सच यह है कि अडाणी की इन कम्पनियों में एलआईसी सहित देश के एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों में जमा आम जनता की ख़ून-पसीने की कमाई को भी झोंका गया है, जो सरकार के तमाम दावों के बावजूद डूब सकता है। वास्तव में भ्रष्टाचार का यह पूरा पहाड़ सरकार की मिलीभगत के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता था। **ऐसा यूँ ही नहीं है कि कभी मोदी जी अडाणी के हवाई जहाज में तो कभी अडाणी मोदी जी के जहाज में यात्रा करते हुए दिख जाते हैं।**

वास्तव में अडाणी से मोदी जी की यह यारी बहुत पुरानी है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही 'इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली' पत्रिका ने तथ्यों के साथ मोदी और अडाणी के बीच के गँठजोड़ को उजागर करते हुए बताया था कि **मोदी सरकार ने अडाणी की कम्पनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एसईज़ेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) सम्बन्धित नियमों में बदलाव किये थे। इतना ही नहीं, अडाणी की कम्पनियों द्वारा करों में चोरी के भी कई आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, ईपीडब्ल्यू के इसी लेख में यह भी बताया गया कि अडाणी की कम्पनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने कस्टम ड्यूटी सम्बन्धित नियमों में भी कई बार फ़ेरबदल किये। इसी तरह पिछले दिनों देश के कई हवाई अड्डों को भी सरकार ने अडाणी को सौंप दिया जिसके लिए तमाम नियम-क़ानूनों में ऐसे बदलाव किये गये जिससे अडाणी द्वारा इन हवाई अड्डों के अधिग्रहण की राह में कोई बाधा ना आये।**

इसके पहले भी अडाणी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमन्त्री मोदी का यार होने के नाते उस की कभी कोई जाँच नहीं की गयी। प्रधानमन्त्री मोदी की यारी का ही नतीज़ा था कि जब कोरोना महामारी के दौर में पूरा देश एक भयंकर आपदा से जूझ रहा था, तो अडाणी-अम्बानी समेत देश के पूँजीपतियों की सम्पत्ति में अरबों-खरबों की बढ़ोत्तरी हो रही थी।

पीएम केयर्स घोटाला: मोदी जी जब फ़िक्र करते हैं, तो भी एक "राष्ट्रवादी" घोटाला हो जाता है!

कोरोना महामारी के दौर में देश की जनता ने जो त्रासदी झेली, उसकी भयावह स्मृतियाँ एक दुःस्वप्न की तरह हमारा पीछा करेंगी। गंगा में तैरती लाशें, अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते-मरते लोगों को कभी भूला नहीं जा सकता। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इस भयंकर आपदा के दौरान किसी अपने को खोया ना हो। देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल चुकी थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस भयंकर आपदा के दौर में 'आपदा को अवसर में बदलने' का नारा उछाला और जनता के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी तो सरकार ने लोगों की सहायता के लिए **पीएम केयर्स** नाम के फण्ड

की घोषणा की। 'पीएम केयर्स' ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री को बनाया गया और इसके सदस्यों में विदेश मन्त्री, गृह मन्त्री और वित्त मन्त्री भी शामिल किये गये। लेकिन इसके बनाने की प्रक्रिया से लेकर इसके ढाँचे तक को देखा जाये तो यह सिवाय धोखाधड़ी और फ्रॉड के और कुछ नहीं था।

सरकार ने ख़ुद इसके बारे में न्यायालय को बताया कि यह एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसमें 'प्रधानमन्त्री' शब्द का केवल इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर है कि यह केवल इसीलिए किया गया ताकि लोग इसे कोई सरकारी योजना समझते हुए बड़े पैमाने पर इसमें दान दें। विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन का एक दिन का पैसा काटकर इस प्राइवेट ट्रस्ट में डालने की घोषणा की गयी। कई जगहों पर तो पहले से मौजूद सरकारी 'प्रधानमन्त्री राहत कोष' के नाम पर कटौती करके उसे इस प्राइवेट ट्रस्ट 'पीएम केयर्स' में जमा करा दिया गया।

इस प्राइवेट ट्रस्ट को हर तरह की पारदर्शिता और जाँच के दायरे से बाहर रखा गया। 'पीएम केयर्स' फ़ण्ड का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा ऑडिट नहीं करवाया जायेगा जो हर सरकारी संस्था के लिए ज़रूरी होता है। इस फ़ण्ड में चाहे जितना मर्ज़ी उतना योगदान किया जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं तय की गयी है। इसमें दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80(जी) के तहत आयकर से छूट दी जायेगी। बाद में वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण और कॉरपोरेट मंत्रालय ने यह भी साफ़ किया कि अगर कम्पनियाँ पैसा देंगी तो इन्हें कम्पनियों की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के मद में शामिल कर लिया जायेगा। सोचने की बात है कि इस मद से कम्पनियाँ अपने इस बजट से राज्यों के 'आपदा राहत कोष' जैसी सरकारी संस्था में दान नहीं कर सकतीं, उस मद से पीएमकेयर्स में पैसे उँड़ेलने की योजना तैयार कर ली गयी। राज्यों को दान करने पर इन कम्पनियों को कोई छूट नहीं मिलने वाली थी। **मतलब पैसा देना हो तो मोदी की झोली में सीधे डालो, और कहीं नहीं! वास्तव में कोरोना महामारी के दौर में मरते हुए लोगों की लाशों पर पीएम केयर्स के नाम पर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया।**

भ्रष्टाचार का यह खेल यहीं नहीं रुका। **बीबीसी द्वारा आरटीआई और अन्य माध्यमों से की गयी जाँच में पता चला कि पीएमकेयर्स फ़ण्ड से वेण्टीलेटर की ख़रीद के लिए ऐसी कम्पनियों को ऑर्डर दिये गये जिनके पहले वेण्टिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। इतना ही नहीं, एक ही तरह की सुविधा वाले**

वेण्टिलेटरों को अलग-अलग कम्पनियों से सात से आठ गुना तक के अन्तर पर ख़रीदा गया।

लेकिन जब घोटाला "रामराज्य" और "धर्मरक्षा" के नाम पर किया जाये, तो वह ख़ुद ही "पवित्र" और "राष्ट्रवादी" हो जाता है। फिर भी भाजपा सरकार के इस "चाल-चेहरा-चरित्र" किसी का ध्यान जाये, तो जनता को उल्लू बनाने के लिए मन्दिर-मस्जिद, हिन्दू-मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, और तमाम फ़र्जी मुद्दों की धुंध फैलाने के लिए गोदी मीडिया तो है ही!

सेण्ट्रल विस्टा घोटाला

इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के इसी दौर में मोदी सरकार ने देश की आम मेहनतक़श जनता गाढ़ी कमाई के पैसों को अपनी ऐय्याशी में उड़ाने का एक नया खेल रचा जिसको 'सेण्ट्रल विस्टा' प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। **सोचने वाली बात है कि जिस देश में एक बहुत बड़ी आबादी (लगभग 36 करोड़) झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथों पर सोती है, वहाँ अपनी ऐय्याशी के लिए सेण्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ खर्च कर डालना वास्तव में देश की ग़रीब व बदहाल जनता का मज़ाक उड़ाना नहीं है? लेकिन यदि यह काम भी "राष्ट्रवादी" तरीके से किया जाये तो ठीक है!** इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होते ही टीवी-चैनलों, मीडिया समेत जगह-जगह यह माहौल बनाया गया कि सेण्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है और इसके बन जाने के बाद देश की आम जनता के जीवन में कितना बदलाव आ जायेगा। देखा जाये तो इंग्लैण्ड समेत यूरोप के तमाम देशों, अमेरिका आदि की संसदों की ईमारतें भारत के संसद भवन से कहीं ज़्यादा पुरानी हैं। लेकिन वास्तव में अपनी झूठी शानो-शौकत दिखाने के लिए न केवल मोदी सरकार ने सेण्ट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट शुरू किया बल्कि कोरोना के दौर में विशेष क़ानून लाकर इसके निर्माण को अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया ताकि इसके निर्माण कार्य में कोरोना के दौर में भी कोई बाधा न आये। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी रक़म अगर महामारी के दौर में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ख़र्च की जाती तो एक बहुत बड़ी आबादी को कोविड की विभीषिका से बचाया जा सकता था। यह भी और कुछ नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई को नेताओं-नौकरशाहों की बकवास और अय्याशी का अड्डा बनाने की ख़ातिर उड़ाना ही था और अपने आपमें एक घोटाला ही था।

राफेल घोटाला

आज़ादी के बाद से ही देश में जीप घोटालों से लेकर बोफ़ोर्स ख़रीद तक, रक्षा घोटालों का लम्बा इतिहास रहा है। जनता के बीच में सेना की छवि को इस तरह से स्थापित किया जाता है कि सेना कोई "दैवीय" चीज़ है जिस पर कोई भी प्रश्न उठाना देशद्रोह होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि "अन्धराष्ट्रवाद" के उन्माद में बहाकर असल सवालों को नज़र से ओझल कर दिया जाये। सेना में तो वास्तव में हमारे ही बेटे-बेटियाँ भर्ती होते हैं, जिनको तमाम अफ़सरान अर्दली मानकर अपमानित करते हैं, जिनके उत्पीड़न से तंग आकर तमाम आम सिपाही आत्महत्याएँ तक कर रहे हैं; जय शाह जैसों को तो अरबपति बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे क्रिकेट का 'ए बी सी' भी नहीं आता। क्या यह ख़ुद एक घोटाला नहीं है? सेना के प्रति भाजपाइयों की इतनी ही भावना है, तो अपने बेटे-बेटियों को भी उन्हें सेना के सिपाहियों के तौर पर भर्ती करवाना चाहिए। **बहरहाल, सेना के नाम पर "राष्ट्रवाद" की फ़र्ज़ी लहर में जनता को बहाने और इस लहर में अपने कुकर्मों को ढँकने का प्रयास करने वाली भाजपा ने पहली बार केन्द्र में सत्ता में आने के साथ ही सैनिकों के ताबूत की ख़रीद में घोटाला करके अपने सच्चे "राष्ट्रवादी" होने का सबूत पेश कर दिया था। दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही भाजपा सरकार ने राफ़ेल ख़रीद के नाम पर नया रिकॉर्ड बना दिया।**

इस घोटाले के पीछे की कहानी यूपीए सरकार के समय से ही शुरू हो गयी थी जब फ़्रांसीसी कम्पनी दसाल्ट ने 2012 में बोली लगाकर भारत को लड़ाकू विमान सप्लाई करने का अधिकार हासिल कर लिया था। समझौता यह था कि भारत सरकार 530 करोड़ रुपये प्रति विमान की दर से 18 विमान ख़रीदेगी और 108 विमानों को भारत सरकार की कम्पनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तकनीक हासिल करके बनायेगी। **लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इस डील को रद्द कर दिया और 1600 करोड़ रुपये प्रति विमान की दर से फ़्रांस की इस कम्पनी से 36 विमान ख़रीदने की घोषणा की।** मोदी सरकार ने दावा किया कि इसके पीछे की वजह यह है कि विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि **इस नये समझौते के पीछे की मुख्य वजह अम्बानी को फ़ायदा पहुँचाना था। इस समझौते से**

सरकारी कम्पनी एचएएल (हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) को ग़ायब कर दिया गया और उसकी जगह दसाल्ट और रिलायंस के बीच वेंचर बना दिया गया। मोदी सरकार सुरक्षा और सेना के नाम पर इस घोटाले की सच्चाई को निगल गयी।

लेकिन मोदी सरकार के गोदी मीडिया ने इस घपले को, जो नंगी आँखों से देखा जा सकता है, "राष्ट्रवाद" और "देशभक्ति" का पर्याय बना दिया। किसी ने सच ही कहा था, **"राष्ट्रवाद सभी उचक्कों, ठगों और बदमाशों की अन्तिम शरणस्थली होता है।"**

प्रतियोगी परीक्षाओं पर पेपर लीक और धाँधली का कहर

भाजपा सरकार के राज में प्रतियोगी परीक्षाओं में धाँधली एक आम बात बन चुकी है। सिविल सर्विसेज़ की परीक्षाओं से लेकर एसएससी तक की परीक्षाओं में पर्चा लीक एक आम नियम बन चुका है। बहुत-सी परीक्षाओं में पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन उनमें भी भ्रष्टाचार और धाँधली एक खुला रहस्य है। हर बार पेपर लीक के बाद सरकार कुछ सॉल्वरों को पकड़कर, किसी अधिकारी-कर्मचारी पर ठीकरा फोड़कर, लीक करने वालों पर सख़्त कार्रवाई करने की बात कह कर खानापूर्ति करने में जुट जाती है। **लेकिन असली बड़े खिलाड़ी कभी सामने नहीं आते।** इतना ही नहीं, इन परीक्षाओं में धाँधली और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलने वाले छात्रों-युवाओं की बात सुनने की बजाय उन पर लाठियाँ बरसायी जाती हैं।

इसी तरह मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में व्यापम घोटाला एक भयंकर ख़ूनी घोटाला साबित हुआ था जिसमें असली अपराधियों को छिपाने के लिए 50 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गयी थी। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आख़िर इस तरह की धाँधली और भ्रष्टाचार की घटनाएँ आखिर होती ही क्यों हैं?

सबसे पहली बात तो यह है आज नेताओं-मन्त्रियों, अधिकारियों, शिक्षा माफ़ियाओं और बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों का एक पूरा तन्त्र सक्रिय है। एसएससी की परीक्षाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में कई बड़ी कोचिंग संस्थाओं का नाम सामने आ चुका है। **इसी तरह पिछले दिनों जनवरी 2020 में भाजपा नेता चन्द्रमा यादव को पुलिस ने टीईटी की परीक्षा में नकल की साज़िश रचते हुए गिरफ़्तार किया था। चन्द्रमा यादव बजरंग दल का विभाग संयोजक और मन्त्री**

सिद्धार्थ नाथ सिंह का प्रतिनिधि भी रह चुका है। ऐसे हो रही है "ख़तरे में पड़े हिन्दू धर्म की रक्षा"! दिन में 'गोरक्षा' और 'लव जिहाद' के नाम पर बेगुनाह अल्पसंख्यकों का क़त्ले-आम करो और रात में नोट छापने के लिए घपले करो! दोगुनी "राष्ट्रसेवा"! **69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का ख़ुलासा करने वाले इलाहाबाद के एक पुलिस अधिकारी का उसके तत्काल बाद ही तबादला कर दिया गया था।** इन परीक्षाओं के पर्चों को भी सरकारी प्रेस से छपवाने की जगह प्राइवेट एजेंसियों से छपवाया जाता है। कई परीक्षाओं में पर्चा लीक होने में प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसों की भागीदारी भी सामने आ चुकी है। **ज़ाहिर है कि सत्ता के पूरे तन्त्र की मिलीभगत के बिना इस तरह का कोई भ्रष्टाचार, धाँधली या पर्चा लीक कराने जैसी घटनाएँ सम्भव नहीं हैं।**

दूसरे, आज के समय मे सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही हैं। सभी पदों को ठेका-संविदा के हवाले किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा की वजह से छात्रों-युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करती है। जिनके पास पैसा-सोर्स आदि है, वह इन परीक्षाओं में हर सम्भव तरीक़े से सेंध लगाकर अपने लिए एक पद हासिल कर लेना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि लाखों रुपये खर्च करके किसी परीक्षा का पर्चा खरीद पाना किसी भी आम छात्र के बस की बात नहीं है।

गोरक्षा का पूरा मामला भी एक भारी घपला ही है। **यदि भाजपा गाय को माता मानती है, तो गोवा में, केरल में, उत्तर-पूर्व के राज्यों में वह माता क्यों नहीं है? वहाँ भाजपा के नेता जनता से ये वायदे क्यों कर रहे हैं कि बीफ़ की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी? अगर गाय माता है तो पूरी दुनिया को बीफ़ की आपूर्ति करने में भारत अव्वल दर्ज़े के देशों में क्यों आता है? भाजपा सारे बूचड़खाने बन्द क्यों नहीं करवा देती? भाजपा नेता सनबोर शुल्लई ने कहा कि चिकन और मटन से ज़्यादा बीफ़ खाना चाहिए। मेघालय के भाजपा नेता अर्नेस्ट मावरी ने कहा "मैं बीफ़ खाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता"! गोरक्षा की नौटंकी करने वाले संघी गुण्डे इनके पीछे क्यों नहीं पड़ते? भाजपा का दंगाई नेता संगीत सोम ख़ुद हलाल मीट का निर्यात करने वाली कम्पनी अल-दुआ का निदेशक था। द्वारका पीठ के स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती ने ही बताया कि अधिकांश बीफ़ निर्यातक कम्पनियों के मालिक ख़ुद भाजपा के ही लोग हैं और मोदी के कार्यकाल में बीफ़ का निर्यात सारे रिकार्ड तोड़ चुका**

है। क्या यह दोमुँहापन नहीं है? वास्तव में, बीफ़ का मसला केवल जनता को मूर्ख बनाकर असली सवालों, यानी रोज़गार, महँगाई, भ्रष्टाचार आदि से जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। अगर हम अब भी इन फ़र्ज़ी मसलों पर बहते हैं, तो यह हमारी मूर्खता होगी और इसकी क़ीमत भी हम ही चुकाएँगे। **भारत जैसे देश में जनवाद का बुनियादी उसूल लागू करके ही फ़ालतू के सिरफुटौव्वल को रोका जा सकता है, कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, कौन-सी भाषा व संस्कृति अपनानी है, कौन-सा काम करना है, और कौन-सा धर्म मानना है या कोई भी धर्म नहीं मानना है, यह हर नागरिक का व्यक्तिगत मसला है और जब तक एक नागरिक दूसरे नागरिक की निजी आज़ादी में कोई दख़लन्दाज़ी नहीं करता, तब तक हर व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का हक़ है।** लेकिन फ़ासीवादी संघ परिवार और भाजपा सरकार इसी बुनियादी लोकतान्त्रिक नियम की धज्जियाँ उड़ाकर ग़ैर-मुद्दों को मुद्दा बनाती है, जनता को आपस में लड़वाती है, गोरक्षा के नाम पर खून-ख़राबा करती है, जबकि इसी के लोग बीफ़ निर्यात करके करोड़पति बनते हैं।

यह भी एक भारी भ्रष्टाचार ही है, जिससे हमें उल्लू बनाया जा रहा है। कम-से-कम अब जाग जाने की ज़रूरत है और बुनियादी लोकतान्त्रिक उसूलों को अपनाने की आवश्यकता है।

एनपीए घोटाला और जनता के ख़ून-पसीने की कमाई को लेकर रफू-चक्कर होते पूँजीपति

मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही एक और नयी परिघटना देश के सामने आयी। **मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी समेत आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी जैसे अनेक पूँजीपति भ्रष्टाचार करके और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर फ़रार हो गये। भारतीय बैंकों में जनता के ख़ून-पसीने से जमा 9,000 करोड़ रुपया डकारकर विजय माल्या के देश से भागने के बाद ख़ुद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके बताया था कि विजय माल्या ने फ़रार होने के एक दिन पहले तत्कालीन वित्तमन्त्री अरुण जेटली से मिलकर अपने लन्दन जाने के बारे में बात की थी।**

इसी तरह भारत से भागकर एण्टीगुआ की नागरिकता लेने वाले मेहुल चौकसी के बारे में ख़ुद वहाँ की सरकार ने बताया कि भारतीय अधिकारियों

द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही वहाँ की नागरिकता दी गयी है। मेहुल चौकसी के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की नज़दीकी किसी से छिपी नहीं है।

अरबों रुपया डकार जाने वाले पूँजीपतियों के अलावा भाजपा सरकार ने देश के पूँजीपतियों को दिये गये क़र्ज़ का बड़ा हिस्सा 'राइट ऑफ़' यानि बट्टा खाते में डाल दिया है जिसकी कभी-भी वसूली नहीं की जायेगी। **पिछले 6 सालों में बैंकों ने क़रीब 11.17 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ 'राइट ऑफ़' किये हैं।** इतना ही नहीं, देश की जनता की ख़ून-पसीने की कमाई से खड़ी की गयी तमाम सम्पत्तियों को भी औने-पौने दामों में इनकी झोलियों में डाल दिया गया है ताकि वे उनमें भी पैसा लगाकर मुनाफ़ा बटोर सकें। वहीं दूसरी ओर, आम ग़रीब आदमी अगर मजबूरी में कोई छोटा-मोटा कर्ज़ लेता है और उसकी वापसी नहीं करता, तो उसकी सम्पत्ति कुर्क होती है या उसे जेल की हवा खानी होती है, जबकि माल्या-मोदी-चौकसी जैसे बैंकों से जनता के अरबों रुपये डकार कर विदेशों में गुलर्छे उड़ाते हैं। **मोदी सरकार ने विदेशों से काला धन लाने की बात की थी, लेकिन असल में मोदी जी के मित्रों ने भारत से लूटकर विदेशों में काले धन की बाढ़ ला दी है! लेकिन सब ठीक है अगर "राष्ट्रवादी" तरीके से "धर्मरक्षा" के लिए यह सब किया जाता है! अगर अब भी हम इनकी "नैतिकता", "कर्तव्य", "संस्कार", "राष्ट्रवाद", "धर्मध्वजारोहण" की बकवास में बहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। सिर्फ़ ज़ोर से "देSSSSSश" बोलने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है! सिर्फ़ ज़ोर से नकियाँकर "विकाSSSSSस" बोलने से कोई प्रगतिशील नहीं हो जाता है! देशप्रेमी और प्रगतिशील होने का अर्थ है शहीदे-आज़म भगतसिंह के समान देश की मेहनतकश जनता के पक्ष में खड़ा होना और लड़ना और परजीवी शोषक धन्नासेठों की सत्ता को नेस्तनाबूद करने की सच्ची लड़ाई करना। क्योंकि देश कोई कागज़ पर बना नक़्शा नहीं होता, बल्कि उसके मेहनतक़श लोगों से बनता है।**

भगतसिंह ने लिखा था कि **क़ानून की पवित्रता तभी तक क़ायम रखी जा सकती है जब तक वह जनता के दिल यानी भावनाओं को प्रकट करता है। जब यह शोषणकारी समूह के हाथों में एक पुर्ज़ा बन जाता है तब अपनी पवित्रता और महत्व खो बैठता है।** आज देश में तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों को क़ानूनी जामा पहनाया जा चुका है। सरकारें पूँजीपतियों के हित में सभी क़ानूनों को

तोड़-मरोड़ देती हैं या उनकी धज्जियाँ उड़ाती रहती हैं। बदले में पूँजीपति वर्ग उनकी पार्टियों को अरबों रुपये चन्दों के रूप में देते हैं। इन पूँजीपतियों टीवी-चैनल और मीडिया चौबीसों घण्टे इनका गुणगान करते हैं ताकि जनता के सामने पूँजीपतियों और पार्टियों के अपवित्र गठबन्धन पर पर्दा डाल दिया जाये। भाजपा के 'सदाचारी' चरित्र को इससे भी समझा जा सकता है कि चुनावी बॉण्ड को अपारदर्शी बनाकर इसने चुनावबाज पार्टियों को मिलने वाले चन्दे को और अधिक रहस्यमय बना दिया गया है, ताकि इस सच्चाई पर पर्दा डाला जा सके। **यह अनायास नहीं है कि 2021-22 में ही अकेले भाजपा को पूँजीपतियों की ओर से 614 करोड़ रुपये का चन्दा प्राप्त हुआ, जबकि इसकी तुलना में पूँजीपति वर्ग की अन्य पार्टियों बहुत कम चन्दा प्राप्त हुआ। क्योंकि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो आज के संकट के दौर में हर तरह के नियमों-क़ानूनों को ताक पर रखकर, हर तरह के भ्रष्टाचार-घोटालों की सहायता लेकर पूँजीपति वर्ग के मुनाफ़े की गिरती दर को पूरा कर सकती है और दूसरी ओर जनता के असन्तोष को जाति-धर्म, मन्दिर-मस्ज़िद, हिन्दू-मुसलमान के नाम पर डायवर्ट कर सकती है।** स्पष्ट है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद का यह संकट बढ़ेगा, भाजपा का चाल-चेहरा-चरित्र भी इसी तरह उजागर होता जायेगा।

हमारी माँगें

- हिण्डेनबर्ग घोटाले, राफ़ेल घोटाले, पीएम केयर्स समेत सभी घोटालों की उच्च स्तरीय जाँच करायी जाये और दोषी पाये जाने वाले सभी कम्पनी मालिकों, प्रबन्धकों और नेताओं को जेल में डाला जाये, चाहे वह प्रधानमन्त्री ही क्यों न हो।
- चुनावी पार्टियों को पूँजीपतियों द्वारा मिलने वाले हर प्रकार के चन्दे का ख़ुलासा किया जाये। पूँजीपतियों द्वारा चुनावी चन्दे को विनियमित किया जाये, उसकी पूरी जाँच की जाये।
- चुनावबाज पार्टियों व सरकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जनता की जनकमेटियों की देखरेख में निगरानी व सार्वजनिक ऑडिट की व्यवस्था की जाये।
- तमाम जाँच व निगरानी संस्थाओं को सरकार के नियन्त्रण से बाहर किया जाये।